



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

मई दिल्ली, सोमवार, जून 25, 1979/प्राषाढ 4, 1901

No. 205]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 25, 1979/ASADHA 4, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न की जाती है जिससे कि यह असाधारण संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मोबहन एवं परिवहन भवान्य

(परिवहन कार्य)

प्रधिकाराद्य

मई दिल्ली, 25 जून, 1979

सं. का. नि. 399 (प्र.) :—कलिपय नियमों का निम्नलिखित मसीदा कलकत्ता पत्रकार्यालयी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अवायायी) नियम, 1975 का संशोधन करते के लिए जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने महा बत्त न्यास प्रधिकारियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उस धारा की उप-धारा (2) द्वारा यथापेक्षित उस सभी अधिकारियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रधायित होने की संभावना है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस सम्प्रसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैतालीस दिनों को अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उस मसीदे पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधायि समाप्त होने से पूर्व उक्त मसीदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से शास्त्र होने वाली भाग्यियों या मुक्तावां पर विचार करेंगी।

नियमों का मस्तक

1. (1) इन नियमों का नाम कलकत्ता पत्रकार्यालयी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अवायायी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रदूष द्दी जाए।

2. कलकत्ता पत्रकार्यालयी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अवायायी) नियम, 1975 में, नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम द्वारा जारीगा, प्रधायित :—

“5 जो न्यासी संघर संवस्य ही या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अवायायी करना :—

नियम 2 और 3 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संघर सदस्य यथा राज्य विधानसभा का सदस्य भी हो, संघर (निर्वहता निवारण) प्रधिकारियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के बच्च (क) में यथापरिमाणित प्रतिशूलक भत्ते की छोड़कर, जेसी भी दिव्यता हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उस भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हों तो, जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार की निर्वहता के बिना राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्वहता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय साधू किसी भी कानून के अधीन भास्त करता हो अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।”

[पी. औ. ए.ल.—१२७८]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, 25th June, 1979

G.S.R. 399(E).—The following draft of certain rules to amend the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975 which

the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975 after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

“5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.”

[PGL-17/79]

सांकेतिक नियम 400(अ) :—शतिष्य नियमों का निम्नलिखित मसौदा बन्धवी पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 का संशोधन करने के लिए जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैंतीलीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उक्त मसौदे पर विचार किया जायेगा ।

केन्द्रीय सरकार उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर विचार करेगी ।

नियमों का मसौदा

1. (1) इन नियमों का नाम बन्धवी पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होगे ।

2. बन्धवी पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 में, नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“5 जो न्यासी संसद सदस्य ही या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना :—

नियम 28और 3 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य भी हो, संपद (निरहंता निवारण)

अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2के बाद (क) में यथापरिभावित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जेसी भी स्थिति हो, यद्युक्ती भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उत्तर भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हों तो, जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार की निरहंता के बिना राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए निरहंता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता ही अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा ।”

[पी० जी० एल०-17/79]

G.S.R. 400(E).—The following draft of certain rules to amend the Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975 after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

“5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State : Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.”

[PGL-17/79]

सांकेतिक नियम 401(अ) :—कतिष्य नियमों का निम्नलिखित मसौदा मद्रास पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 का संशोधन करने के लिये जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैंतीलीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उक्त मसौदे पर विचार किया जायेगा ।

केन्द्रीय सरकार उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर विचार करेगी ।

नियमों का अद्वैत

1. (1) इन नियमों का नाम मद्रास पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अवायवी) संशोधन नियम, 1979 है।
- (2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रयुक्त होने।
2. मद्रास पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अवायवी) नियम, 1975 में, नियम 2 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्:—

“ 3 जो न्यासी मंसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अवायवी करना:—

नियम 2 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो सदब सदस्य अवधार राज्य विधानसभा का सदस्य भी हो, संघर (निरहुता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यापारिमाणित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हो तो, जिन्हे राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार की निरहुता के बिना राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिये निरहुता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय जागू किसी भी कामन के अधीन प्राप्त करता हो अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।

[पी० जी० एल०-17/79]

G.S.R. 401(E).—The following draft of certain rules to amend the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules 1975 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975 after rule 2, the following rule shall be inserted, namely:—

“3. Payment of certain allowance to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State: Notwithstanding anything contained in rule 2 a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.”

[PGL-17/79]

सा०जा०पि० 402(अ)—नियमों का निम्नलिखित मसौधा नूसीकोरिंग पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों की शुल्क और भत्तों की अवायवी) नियम, 1979 का संशोधन करने के लिये जिन्हे नैसीय वरकार ने महा-पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963

का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रस्तुत विवरों का प्रबोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उक्त धारा को उपधारा (2) द्वारा यथाप्रेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभवता है और यह सुनित किया जाता है। कि इस प्रधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर प्रेतालोक दिनों की प्रबंध समाप्त होने पर या उसके उसके बाद उक्त मसौधे पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिसूचना समाप्त होने से पूर्व उक्त मसौधे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपसियों वा सुनावों पर विचार करेगी।

नियमों का अद्वैत

1. (1) इन नियमों का नाम तूतीकोरिन पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अवायवी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रयुक्त होंगे।

2. तूतीकोरिन पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अवायवी) नियम, 1979 में, नियम 3 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्:—

“ 4. जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अवायवी करना:—

नियम 2 और 3 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद सदस्य अवधार राज्य विधानसभा का सदस्य भी हो, संघर (निरहुता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यापारिमाणित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हो तो, जिन्हे राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार की निरहुता के बिना राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिये निरहुता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय जागू किसी भी कामन के अधीन प्राप्त करता हो अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।”

(पी०जी०हस०-17/79)

G.S.R. 402(E).—The following draft of certain rules to amend the Board of Trustees of the Port of Tuticorin (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1979 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Tuticorin (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Tuticorin (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1979 after rule 3 the following rules shall be inserted, namely:—

“4. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance

as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

[POL-17/79]

सं०क्षणि० 403(प्र)—कलिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा मार्गिगार्थो पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1964 का संशोधन करने के लिये जिन्हें केन्द्रीय सरकार महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त गमितियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उक्त धारा को उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है जिनको उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैतालीय दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उक्त मसौदे पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना के से पूर्व उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या मुशायों पर विचार करेगी।

नियमों का मसौदा

1. (1) इन नियमों का नाम मार्गिगार्थो पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मार्गिगार्थो पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1964 में, नियम 3 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“5. जो न्यासी संसद् सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना:

नियम 3 और 4 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद् सदस्य अधिकार राज्य विधान सभा का सदस्य भी हो, संसद् (निरहृता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के अध्य (क) में यथापरिमाणित प्रतिपूरक भत्तों को छोड़कर जैसी भी स्थिति हो, अर्थ किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हो तो, जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार के निरहृता के बिना राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिए निरहृता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो अर्थ किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।

[पी०जी०एल०-17/79]

G.S.R. 403(E).—The following draft of certain rules to amend the Mormugao Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Mormugao Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mormugao Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules 1964, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:—

“5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State: Notwithstanding anything contained in rules 3 and 4, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.”

[F. No. PGL-17/79]

सं०क्षणि० 404(प्र)—कलिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा पारावीप पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1967 का संशोधन करने के लिये जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त गमितियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उक्त मसौदे पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना के से पूर्व उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या मुशायों पर विचार करेगी।

नियमों का मसौदा

1. (1) इन नियमों का नाम पारावीप पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पारावीप पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1967 में, नियम 3 के बाद निम्नलिखित नियम रखा जायेगा अर्थात्:—

“4. जो न्यासी संसद् सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना:

नियम 2 और 3 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद् सदस्य अधिकार राज्य विधान सभा का सदस्य भी हो, संसद् (निरहृता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के अध्य (क) में यथापरिमाणित प्रतिपूरक भत्तों को छोड़कर जैसी भी स्थिति हो, अर्थ किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हो तो, जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार के निरहृता के लिए बिना राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिए निरहृता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो अर्थ किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।

[पी०जी०एल०-17/79]

G.S.R. 404(E).—The following draft of certain rules to amend the Paradip Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1967, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963

(38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Paradip Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Paradip Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1967, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely :—

“4. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State : Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.”

[F. No. PGL-17/79]

सांकेतिक 405(प्र).—कर्तिपय नियमों का निम्नलिखित मर्यादा महा पत्रम् न्यास (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की भवायारी) नियम, 1964 का संशोधन करने के लिये जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने महा पत्रम् न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपचारा (1) द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उक्त धारा की उपचारा (2) द्वारा यथाधर्मेष्ठि उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचित किया जाता है कि इस व्यक्ति-मूलभा के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैतालीस दिनों की अवधि मरात्त होने पर या उसके बाद उक्त मर्यादे पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय मरात्त उक्त व्यक्ति मरात्त होने से पूर्व उक्त मर्यादे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपलियों या सुझावों पर विचार करेगी।

नियमों का असाधारण

1. (1) इन नियमों का नाम महा पत्रम् का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की भवायारी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. महा पत्रम् का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की भवायारी) नियम, 1964 में, नियम 4 के बाद निम्नलिखित नियम रखा जायगा, प्रथम :—

“5. जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की भवायारी करना :—

नियम 3 और 4 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद सदस्य भव्यवा राज्य विधान सभा का सदस्य हो, संसद (निरहूता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) को धारा 2 के खण्ड (क.) में यथा परिभाषित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर मदि कोई हो, तो जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार के निरहूता के बिना राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिये निरहूता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अवधीन प्राप्त करता हो अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।

[पी०जी०एस०-17/79]

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

G.S.R. 405(E).—The following draft of certain rules to amend the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

“5. Payment of certain allowance to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State : Notwithstanding anything contained in rules 3 and 4, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification”

[F. No. PGL-17/79]

D. K. JAIN, Jt. Secy.

